

स्विट्जरलैंड के साथ भारत की बड़ी डील...10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का निवेश

भारत-स्विट्जरलैंड साझेदारी के तीन मजबूत स्तंभ इनोवेशन,इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली,05 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पारमेली के बीच सोमवार को हैदराबाद हाउस में अहम द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-स्विट्जरलैंड संबंधों को खास बताते हुए कहा कि इनोवेशन,इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दोनों देशों की साझेदारी के तीन मजबूत स्तंभ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन की बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्ते नए दौर में प्रवेश कर गए हैं। अब सहयोग सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। दोनों देश निवेश, निर्यात, रक्षा,परमाणु ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में मिलकर काम बढ़ाएंगे। स्विट्जरलैंड में भारतीय सामान की बिक्री बढ़ाने और वहां से ज्यादा निवेश भारत लाने पर सहमति बनी है। दरअसल, पीएम मोदी और स्विस् राष्ट्रपति गाइ पारमेलिन के बीच वार्ता के बाद,भारत और स्विट्जरलैंड ने सोमवार को आब्रजन और आवाजाही साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही, उन्होंने भारतीय निर्यात के लिए स्विस् बाजार तक पहुंच बढ़ाने और परमाणु ऊर्जा व रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति जताई। बता दें कि पारमेलिन सोमवार सुबह तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे,जो उनकी इस देश की पहली आधिकारिक यात्रा है। हालांकि,इस वर्ष वह दूसरी बार आयाजिए हैं। वह इससे पहले फरवरी में भारतो गए। 'एआई ईपैक्ट शिखर सम्मेलन' में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अपने

निर्यात बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के फैसले
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने भारत के निर्यात को स्विट्जरलैंड में अधिक बाजार पहुंच देने और अपनी निवेश को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे कृषि,कामा, टेक्साटाइल और इंजीनियरिंग मुद्रा के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत के वायोटैक,लव्हा साइलेंज, बैकिंग,इन्फ्रास्ट्रक्चर,ग्रोसरेसिंग और रास्टनेमिलिट्री जैसे क्षेत्रों में नए रिसा निवेश को आकर्षित करने पर सहमति बनी है।
एमओयू का आदान-प्रदान भी हुआ
संयुक्त इस वार्ता से पहले दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और स्विस् परिबंध के बीच एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। स्विस् राष्ट्रपति गी पारमेली तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। सोमवार को दिल्ली पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था।



मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के देशों-आइसलैंड,लिकटेनस्टीन,नॉर्वे और स्विट्जरलैंड-के बीच 'व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता' (टीईपीए) के अक्टूबर में लागू होने से दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश के रिश्तों को और बढ़ावा मिला है। मोदी ने कहा कि टीईपीए निवेश,नवाचार, रोजगार और साझा समृद्धि के लिए एक 'महत्वाकांक्षी खाका' है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से,हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अपने लक्ष्यों को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री ने नवाचार,बुनियादी ढांचे और उन्नत प्रौद्योगिकी को भारत-स्विट्जरलैंड साझेदारी के मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि दोनों पक्ष सहभागिता को 'नई गति' देने जा रहे हैं।

ईएफटीए के साथ ऐतिहासिक समझौते में स्विट्जरलैंड का प्रथम योगदान
पीएम मोदी ने स्विस् राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा... 'सबसे पहले मैं भारत-स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। पिछले वर्ष उनके समर्थन से हमने भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है।
रक्षा और न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग बढ़ाएंगे...

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों पक्षों ने सैन्य आदान-प्रदान (मिलिट्री एक्सचेंज) और रक्षा उत्पादन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की है। साथ ही परमाणु ऊर्जा (न्यूक्लियर एनर्जी) में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी है।

मोदी ने स्विस् राष्ट्रपति को भेंट की भारतीय चीज की तीन विशेष किस्में,कश्मीरी अखरोट पैनल भी दिया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पारमेलिन को भारत में तैयार की गई चीज की तीन विशेष किस्में 'गुलमर्ग', 'कोणार्क' और 'यूर' भेंट की। इसके अलावा उन्होंने स्विस् राष्ट्रपति को कश्मीरी पारंपरिक कला को दर्शाने वाला अखरोट की लकड़ी से बना हस्तनिर्मित दीवार पैनल भी उपहार में दिया। 'गुलमर्ग' फ्रांसीसी शैली का नरम और क्रीमी चीज है, जिसे पाश्चुरीकृत गाय के दूध से तैयार किया जाता है। इसे 2026 के 'मुंडियल डू फ्रांमाज डू ब्राजील' में 'सुपर गोल्ड' सम्मान मिला है। 'कोणार्क' फ्रांसीसी टोम शैली का चीज है,जिसे 2023 में नॉर्वे में आयोजित 'वर्ल्ड चीज अवार्ड्स' में स्वर्ण और 2025 में स्विट्जरलैंड में रजत सम्मान मिला था। 'यूर' पर्वतीय शैली का चीज है, जिसे स्विस् मुईथर से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया है।

आजादी के बाद पहली बार डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ अंतरराष्ट्रीय मालवाहक जहाज



नई दिल्ली,05 अक्टूबर 2026। असम के डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबील टर्मिनल से आजादी के बाद पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य के लिए मालवाहक जहाज रवाना किया गया। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 540 मीट्रिक टन मेथेनॉल लेने वाले को हरी झंडी दिखाकर बांग्लादेश के ढाका के लिए रवाना किया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा आभासी माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह मेथेनॉल राज्य की

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड द्वारा नामरूप में उत्पादित किया गया है। मालवाहक पोत बोगीबील से ढाका के पांगांव बंदरगाह तक लगभग 1,300 किलोमीटर की यात्रा करेगा। इसमें भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर लगभग 768 किलोमीटर का मार्ग और उसके बाद भारत-बांग्लादेश फ्रोटोकॉल मार्ग शामिल है। सोनोवाल ने कहा कि डिब्रूगढ़ कभी पूर्वी भारत के सबसे व्यस्त नदी बंदरगाहों में गिना जाता था। 70 वर्षों तक यहां स्टीमर की सीटी खामोशी रही, लेकिन आज डिब्रूगढ़ से एक बार फिर दुनिया की ओर

जहाज रवाना हो रहा है। उन्होंने इसे असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि यह असम के लिए गर्व का दिन है क्योंकि राज्य में निर्मित उत्पाद अब राज्य की अपनी नदी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है। पूर्वोत्तर अब देश का सीमावर्ती क्षेत्र नहीं,बल्कि पूर्व की ओर भारत का प्रवेश द्वार बन रहा है। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि यह केवल शुरुआत है। नरेंद्र मोदी की सरकार डिब्रूगढ़ को उसके ऐतिहासिक नदी बंदरगाह वाले गौरव से फिर जोड़ने के लिए प्रयासरत है।

एसआईआर प्रेस नोट विवाद...चुनाव आयोग ने दावों को नकारा कहा-वेबसाइट से कभी हटाया ही नहीं,फॉर्म 6 पर क्या कहा?



नई दिल्ली,05 अक्टूबर 2026। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने सोमवार को उन दावों को खारिज किया कि 26 सितंबर को जारी प्रेस नोट को उसकी वेबसाइट से हटा दिया गया था। आयोग के सूत्रों ने कहा कि यह प्रेस नोट अभी भी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे कभी हटाया नहीं गया। 26 सितंबर के इस प्रेस नोट में आयोग ने फॉर्म 6 से जुड़ी कुछ शर्तों में बदलाव की जानकारी दी थी। इसके साथ ही बृथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को मतदाताओं के घर जाकर नोटिस से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
वेबसाइट से नहीं हटाया गया प्रेस नोट : चुनाव आयोग
आयोग ने पिछले महीने जारी इस नोट में दिल्ली और महाराष्ट्र में एसआईआर की समयसीमा बढ़ाने की जानकारी भी दी थी। इसके अलावा आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आयोग से मांगा जवाब
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की शक्तियों के इस्तेमाल के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत के सामने यह सवाल उठाया गया कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियों का व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल या प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीनों निर्वाचन आयुक्तों से भी जवाब मांगा। पीठ में न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी कि निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है और मुख्य चुनाव आयुक्त उस वैधानिक व्यवस्था के विपरीत काम कर रहे हैं, जो आयोग के कामकाज को नियंत्रित करती है।
पहले प्रमाणित जानकारी मांगेगा सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत को सबसे पहले आरोपों के संबंध में प्रमाणित जानकारी की जरूरत होगी। अदालत ने कहा कि अगर बाद में किसी फैसले को गैरकानूनी पाया जाता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'पहले हमें उसके बारे में प्रमाणित जानकारी चाहिए। हम किसी भी फैसले को बाद में रद्द कर सकते हैं।' विकास सिंह ने वैकल्पिक रूप से मांग की कि अगली सुनवाई तक निर्वाचन आयोग के फैसले केवल सर्वसम्मति से लिए जाने का निर्देश दिया जाए।

भाजपा ने उप से राज्यसभा के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित

नई दिल्ली,05 अक्टूबर 2026। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए आठ उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी तरुण चुग ने सोमवार को इन आठ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जिन आठ नेताओं को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है उनमें धर्मपाल सिंह,राधाकांत ओझा,प्रकाश पाल,विद्यासागर सोनकर,गोपी कृष्ण पाण्डेय,प्रियंका सिंह रावत,रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं। धर्मपाल सिंह अभी उत्तरप्रदेश सरकार में मंत्री हैं। प्रकाश पाल को हाल ही में भाजपा ने प्रदेश ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। प्रियंका सिंह रावत बाराबांकी से सांसद रह चुकी हैं और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष हैं। राधाकांत ओझा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। विद्यासागर सोनकर एससी समाज से है। एक बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से जारी है। उम्मीदवार 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा।



कूनों में पांच शावकों का जन्म प्रोजेक्ट चीता के लिए ऐतिहासिक पल : भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली,05 अक्टूबर 2026। मध्य प्रदेश के इंदोपुर स्थित कूनों राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय धरती पर जन्मी मादा चीता केजेपी21 के पांच स्वस्थ शावकों को जन्म देने पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे प्रोजेक्ट चीता के लिए एक और ऐतिहासिक खुशी का क्षण बताया। केजेपी21 की उम्र 32 महीने है और वह भारत में जन्मी तीसरी मादा चीता है, जिसने देश में शावकों को जन्म दिया है।

देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल,असम तमिलनाडु और पुडुचेरी में उपचुनाव आज

प.बंगाल की दो सीटों पर उपचुनाव,15 साल में पहली बार ममता न सीएम-विधायक,न उम्मीदवार

नई दिल्ली,05 अक्टूबर 2026।देश के चार राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज उपचुनाव होगा। इसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की दो-दो विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं पुडुचेरी में एक विधानसभा और असम में एक लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। सबसे अहम पश्चिम बंगाल है जहां 15 साल में पहली बार ऐसा चुनाव होगा। जब ममता बनर्जी राज्य में न तो सीएम हैं, न ही विधायक और न उम्मीदवार। मई में आए विधानसभा चुनाव रिजल्ट में टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई थी। ममता भी अपनी सीट हारी थीं। पहले चर्चा थी कि वे नंदीग्राम से उपचुनाव लड़ सकती हैं लेकिन उन्होंने वहां से संचिता प्रधान को टिकट दिया। बाद में संचिता चुनाव से पीछे हट गईं। अब इस सीट पर ममता का कोई कैंडिडेट नहीं है। बंगाल में दूसरी सीट रेजीनगर पर वोटिंग होगी। सभी सीटों पर रिजल्ट 9 अक्टूबर को होगा।



चंद्रनाथ रथ की मां को उम्मीदवार बनाया है। चंद्रनाथ रथ की 6 मई 2026 को हत्या कर दी गई थी।
नंदीग्राम टीएमसी और भाजपा, दोनों के लिए अहम सीट : नंदीग्राम लंबे समय से टीएमसी और भाजपा के बीच राजनीतिक संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने ममता बनर्जी और टीएमसी को 2011 में सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 2021 में ममता ने यहीं से बंगाल के मौजूदा सीएम शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। अधिकारी बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बन चुके हैं। 2026 के विधानसभा

चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीत दर्ज की। भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया। अधिकारी को 73,917 वोट मिले,जबकि ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले।
रेजीनगर में मुश्किल मुकाबला;
बीजेपी, कांग्रेस,ममता,हुमायूं के कैडिडेट : रेजीनगर में बीजेपी, कांग्रेस,टीएमसी के दोनों धड़ों,CPI(M) और हुमायूं कबीर की पार्टी जनता उन्नयन पार्टी मैदान में हैं। रेजीनगर मुस्लिम बहुल सीट है। बीजेपी के शंकराव सरकार को छोड़कर सभी प्रमुख उम्मीदवार मुस्लिम हैं।

फॉर्म 6 में किया अवैध-एकतरफा बदलाव राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर हमला कहा- पद के दुरुपयोग का एक और सबूत



नई दिल्ली,05 अक्टूबर 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने मतदाता पंजीकरण से जुड़े फॉर्म 6 में गैरकानूनी और एकतरफा तरीके से बदलाव किया। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह बात बिना किसी शक के स्थापित हो गई है। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, 'अब यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो गया है कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में अवैध और एकतरफा तरीके से बदलाव किया। यह भाजपा की मदद के लिए उनके पद के दुरुपयोग का एक और सबूत है। लोकतंत्र पर इस आपराधिक हमले में शामिल वह और बाकी सभी लोग जवाबदेह ठहराए जाएंगे।' राहुल गांधी ने अपने दावे के समर्थन में निर्वाचन आयोग की एक पुरानी प्रेस विज्ञप्ति की तस्वीर भी साझा की। दरअसल,यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले संशोधित फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी है। यह फॉर्म विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, 'किसी भी संशोधित फॉर्म 6 को हमने मंजूरी नहीं दी है। यह स्पष्ट है। रिकॉर्ड सामने आने पर हम देखना चाहेंगे कि इसमें बदलाव किसने किया।'

संपादकीय



अगले सुधारों की पुख्ता तैयारी

विकसित भारत बनने के भारत के संकल्प के लिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें हर स्तर और आकार के उद्यम फल-फूल सकें, चाहे उनकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो। पिछले बारह वर्षों में हमारी सरकार ने इन अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2017 में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने से अप्रत्यक्ष कराधान के लिए एक साझा राष्ट्रीय ढांचा स्थापित हुआ। नेक्स्ट-जेनरेशन का जीएसटी नौ वर्षों के क्रियान्वयन तथा करदाताओं और राज्यों के अनुभवों के आधार पर इसी प्रयास को आगे बढ़ाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप,नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी की परिकल्पना दो परस्पर जुड़े उद्देश्यों के साथ की गई थी कर दरों को कम एवं तर्कसंगत बनाना और अनुपालन को अधिक सरल बनाना। दरों में किए गए संशोधन 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी हुए। प्रक्रियात्मक सुधारों का अगला चरण शीघ्र ही जीएसटी परिपद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सम्मिलित रूप से, इन प्रयासों का उद्देश्य परिवारों को राहत देना,व्यवसायों को अधिक निश्चिन्ता प्रदान करना और करदाताओं के लिए एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करना है जिसमें वे बिना किसी अनावश्यक कठिनाई के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। राज्य इस पूरी यात्रा में बराबर के साझेदार रहे हैं। वे परिपद में अपनी प्राथमिकताओं और अनुभवों को लेकर आए,निर्णयों को आकार देने में सहयोग किया और उनके क्रियान्वयन का दायित्व संभाला। जीएसटी की प्रगति प्रत्येक सरकार के उत्तरदायित्वों का सम्मान करते हुए एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की इसी तत्परता पर टिकी है।

इसके परिणाम विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच दर्ज की गई कर-योग्य आपूर्ति के मूल्य में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर दरों की हल्की संरचना के साथ-साथ दर्ज आर्थिक गतिविधियों में भी व्यापक विस्तार देखा गया है। यह उस सुधार के लिए एक अत्यंत उत्साहवर्धक आधार है जिसका उद्देश्य उद्यमों और सार्वजनिक वित्त,दोनों को संबल प्रदान करना है। यह सुदृढ़ता हालिया राज्यस्व आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई देती है। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 12.46 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया,जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 11.6 प्रतिशत अधिक है। जून से सितंबर तक के प्रत्येक महीने में वार्षिक आधार पर दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। इन चार महीनों का कुल संग्रह मिलकर लगभग 15 प्रतिशत की गति से बढ़ा। कर वापसी (रिफंड) के बाद शुद्ध संग्रह में भी इस छमाही के दौरान 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार करदाताओं की दी गई राहत और विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि साथ-साथ हुई है।

इस विस्तार का दायरा उसके पैमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। सभी 11 क्षेत्रक समूहों और सभी प्रमुख राज्यों में दर्ज कर-योग्य आपूर्ति में वृद्धि देखी गई। भारत जैसी विविध अर्थव्यवस्था में यह व्यापक प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक हिस्सों में होने वाली यह वृद्धि अधिक से अधिक व्यवसायों को विस्तार लेते बाजारों में भाग लेने का अवसर देती है और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न मांग,निवेश तथा रोजगार से अधिकाधिक समुदायों को लाभान्वित करती है। जब कर राहत का प्रभाव कीमतों में दिखाई देता है,तो परिवारों के पास अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने या बचत करने के लिए अधिक गुंजायमान होती है। उपभोक्ता राहत और उद्यम विकास आपस में गहराई से जुड़े हैं। परिवारों की र्ग्य शक्ति व्यवसायों द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बनाए रखती है। इसका लाभ परिवार से लेकर खुदरा विक्रेता,आपूर्तिकर्ता और उत्पादक तक पहुंचता है।

सपा-कांग्रेस को वही मिल रहा है...

जिसके लिये वह डिजर्व करती है...



संजय सक्सेना
 लखनऊ, उत्तरप्रदेश

भारतीय राजनीति में तुष्टिकरण और वोट बैंक की सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन वर्तमान दौर में यह बखस एक नए चरम पर पहुंच चुकी है। हाल के दिनों में देश की राजनीति में जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले हैं,उसने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस की नीतियों और नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता के एक बड़े वर्ग का मानना है कि कांग्रेस आज उस चौराहे पर खड़ी है जहां वह वही काट रही है जो उसने बोया है। तुष्टिकरण की राजनीति में हद से आगे बढ़ जाने का आरोप झेल रही कांग्रेस पर यह लॉखन लग रहा है कि वह बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की अनदेखी करके और कुछ विशेष वर्गों को रखाने के चक्कर में देश के स्वाभिमान तक से समझौता करने की तैयार दिखती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों को लेकर अक्सर यह आलोचना होती है कि राष्ट्रहित से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर भी उनका रुख देश की सामूहिक भावना के विपरीत नजर आता है।

इस पूरे विमर्श को हाल ही में हुई एक बेहद संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय घटना ने और हवा दे दी है। दुबई से इजरायल जा रहे एक विमान को हाईजैक करके 09/11 जैसी भयानक त्रासदी को दोहराने की साजिश रची गई थी। इस विमान को एक हिंदुस्तानी पायलट स्मित मच्छर उड़ा रहे थे। कैप्टन स्मित मच्छर ने जिस अदम्य साहस, सूझबूझ और जांबाजी का परिचय दिया, उसने न केवल सैकड़ों बेगुनाह यात्रियों की जान बचाई,बल्कि दुनिया को एक और भीषण आतंकी हमले से भी महफूज रखा। अपनी जान पर खेलकर देश का नाम रोशन करने वाले इस जाबजबा पायलट की तारीफ पूरी दुनिया में हुई और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देश की जनता उम्मीद कर रही थी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर राजनीतिक दल इस नायक की सराहना करेगा, लेकिन इस मोर्चे पर कांग्रेस आलाकमान की रहस्यमयी खामोशी ने हर किसी को हैरान और आक्रोशित कर दिया। जब पूरा देश कैप्टन स्मित मच्छर के शौर्य को सलाम कर रहा था, तब कांग्रेस की यह चुप्पी आम लोगों को खटकने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि पार्टी को शायद इस बात का डर था कि एक भारतीय नायक की खुलकर तारीफ करने से उसका एक खास वोट बैंक नाराज न हो जाए।

इस मामले में सियासत तब और गरमा गई जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता और पार्टी के रणनीतिकारों में शामिल इमरान मसूद का एक विवादास्पद बयान सामने आया। इमरान मसूद ने कैप्टन स्मित मच्छर की इस ऐतिहासिक जांबाजी और बहादुरी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रयोजित किए «इवेंट» करार दे दिया। देश की सुरक्षा और एक सैनिक या सशस्त्र के शौर्य को राजनीतिक इवेंट बताना न केवल उस बहादुर कप्तान का अपमान है, बल्कि देश की सुस्था एजेंसियों और राष्ट्र की अस्मिता पर भी चोट है। इमरान मसूद का यह बयान कांग्रेस की उस मानसिकता को उजागर करता है जिसमें देश के गौरव को भी शुद्ध रूप से चुनावी नफा-नुकसान के चरमे से देखा जाता है। यूपी प्रधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े इस समय में कांग्रेस अपनी इस कथित तुष्टिकरण की नीति का प्रयोग कर राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनता अब इन चालों को समझने लगी है।

एशियाड का चौथा स्थान प्रथम बनने का संकल्प बने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में खेलों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदला है। खेल अब केवल मनोरंजन या कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों का क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि इसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठ,युवा शक्ति और स्वस्थ समाज के निर्माण से जोड़ा जा रहा है। भारत की अगली चुनौती केवल पदक जीतना नहीं,बल्कि लगातार चैंपियन तैयार करना है। एक खिलाड़ी की सफलता के बाद उसी खेल में अगली पीढ़ी तैयार होनी चाहिए। इसके लिए खेल विज्ञान को प्रशिक्षण का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। आधुनिक फिटनेस,डेटा विश्लेषण,बायोमैकेनिक्स,स्पोर्ट्स मेडिसिन,मनोविज्ञान और पोषण विज्ञान को भारतीय खेल व्यवस्था में व्यापक रूप से शामिल करना होगा। मानसिक मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा के साथ दबाव संभालने की क्षमता निर्णायक बनती है...



ललित गर्ग,
 पटपडगांव,दिल्ली

एशियाई खेलों में भारत का चौथे स्थान पर रहना निश्चित रूप से उपलब्धि है,लेकिन विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखने वाले भारत के लिए यह उपलब्धि आत्मसंतोष का कारण नहीं,बल्कि आत्मसमंथन और नए संकल्प का अवसर होनी चाहिए। आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 85 पदक-21 स्वर्ण,27 रजत और 37 कांस्य-जीतकर अपनी क्षमता का परिचय दिया है। एशिया जैसे खेल महाशक्ति वाले महाद्वीप में शीर्ष चार देशों में स्थान बनाना सामान्य उपलब्धि नहीं है। फिर भी प्रश्न यह है कि जब चीन और जापान जैसे देश हमसे आगे हैं,तब भारत प्रथम और द्वितीय स्थान तक कब पहुंचेगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस भारत को हम आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सामरिक दृष्टि के रूप में विश्व की अग्रिम पंक्ति में देखना चाहते हैं,उसकी खेल शक्ति अभी भी अपेक्षित ऊंचाइयों तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? एशियाड के पदक हमें दो अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उत्साह जगाती है। तीरंदाजी में नौ पदक,जिनमें पांच स्वर्ण शामिल हैं,भारतीय प्रतिभा की मजबूत उपस्थिति का प्रमाण है। कुमुकुम मोहोद का रिकर्व वर्ग में व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करना,प्रणवी उर्स का व्यक्तिगत गोल्फ स्वर्ण

जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनना तथा बॉक्सिंग और कुश्ती में स्वर्णिम प्रदर्शन हमारी खेल प्रतिभा की व्यापकता को दर्शाता है। क्रिकेट,हॉकी और कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा भी कायम रहा।

महिला हॉकी टीम की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मौजूदा चैंपियन चीन को हराकर स्वर्ण पदक हासिल करना केवल एक पदक नहीं,बल्कि चार दशक से अधिक समय से चले आ रहे इंतजार का अंत है। यह जीत बताती है कि जब प्रतिभा, अनुशासन,सामूहिक भावना और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता एक साथ आती है तो भारतीय खिलाड़ी किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आत्मसंथन की मांग करती है। एथलेटिक्स में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं हुआ। निशानेबाजी, जिसे भारत की पदक संभावनाओं का मजबूत आधार माना जाता है,भी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी। पिछली बार के मुकाबले कुल पदकों और स्वर्ण पदकों में कमी भी गंभीर संकेत है। इसलिए चौथा स्थान हमारी मंजिल नहीं,अगली छलांग का पड़ाव होना चाहिए।भारत और चीन-जापान के बीच अंतर को केवल पदक तालिका से नहीं समझा जा सकता। खेलों में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए वर्षों तक चलने वाली वैज्ञानिक योजना,जमीनी स्तर से प्रतिभा खोज,आधुनिक प्रशिक्षण,खेल विज्ञान, पोषण,मानसिक मजबूती,चिकित्सा सहायता और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का निरंतर अनुभव जरूरी होता है। चीन ने खेलों को राष्ट्रीय शक्ति के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में विकसित किया है। जापान ने खेल संस्कृति को शिक्षा,अनुशासन और जीवनशैली से जोड़ा है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह अपनी विशाल युवा आबादी को केवल संभावित खिलाड़ियों की संख्या के रूप में न देखे,बल्कि उसे विश्वस्तरीय खेल प्रतिभा में बदलने का तंत्र उपस्थिति का प्रमाण है। कुमुकुम मोहोद का रिकर्व वर्ग में व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करनी नहीं है। कमी है तो प्रतिभा को पहचानने,तराशने और लंबे समय तक

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने वाली सुव्यवस्थित व्यवस्था की। गांव,छोटे शहर और साधारण परिवारों से आने वाली असंख्य प्रतिभाएं आज भी उचित प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर के अभाव में आगे नहीं बढ़ पातीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में खेलों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदला है। खेल अब केवल मनोरंजन या कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों का क्षेत्र नहीं रह गया है,बल्कि इसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठ, युवा शक्ति और स्वस्थ समाज के निर्माण से जोड़ा जा रहा है। खेलो इंडिया जैसे अभियानों ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को पहचानने की दिशा में महत्वपूर्ण वातावरण बनाया है। ओलंपिक और एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की बढ़ती उपस्थिति भी इस परिवर्तन का संकेत है। लेकिन अब अगला चरण और अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए। हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि भारत कितने पदक जीत सकता है, बल्कि यह पूछना चाहिए कि भारत किन खेलों में विश्व की शीर्ष शक्ति बन सकता है। हमें पदक-केन्द्रित सोच से आगे बढ़कर खेल-परिस्थितिकी तंत्र यानी ऐसी पूरी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें प्रतिभा की खोज से लेकर उसके अंतरराष्ट्रीय करियर तक हर चरण की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। भारत में खेल और शिक्षा को लंबे समय तक एक-दूसरे का विकल्प समझा गया। यह सोच बदलनी होगी। खेल किसी विद्यार्थी के पढ़ाई में बाधा नहीं,बल्कि उसके व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम है। विद्यालयों में खेल के घंटे, प्रशिक्षित कोच,आधुनिक मैदान और फिटनेस कार्यक्रम अनिवार्य होने चाहिए। यदि किसी बच्चे में असाधारण प्रतिभा छुपी हो, तो उसकी आर्थिक स्थिति उसके भविष्य की बाधा नहीं बननी चाहिए। सरकारी,निजी क्षेत्र,खेल संस्थाओं और कॉरपोरेट जगत को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी,जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ी को प्रशिक्षण,उपकरण,पोषण, यात्रा और प्रतियोगिताओं के लिए आर्थिक



सुरक्षा मिल सके।

भारत की अगली चुनौती केवल पदक जीतना नहीं, बल्कि लगातार चैंपियन तैयार करना है। एक खिलाड़ी की सफलता के बाद उसी खेल में अगली पीढ़ी तैयार होनी चाहिए। इसके लिए खेल विज्ञान को प्रशिक्षण का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। आधुनिक फिटनेस,डेटा विश्लेषण, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन, मनोविज्ञान और पोषण विज्ञान को भारतीय खेल व्यवस्था में व्यापक रूप से शामिल करना होगा। मानसिक मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा के साथ दबाव संभालने की क्षमता निर्णायक बनती है। इसलिए खिलाड़ियों के लिए खेल मनोवैज्ञानिकों और मानसिक प्रशिक्षकों की नियमित व्यवस्था आवश्यक है। किसी खिलाड़ी की एक प्रतियोगिता में असफलता को उसकी क्षमता का अंतिम प्रमाण मानने के बजाय उसे सीखने और वापसी का अवसर दिया जाना चाहिए। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने हाल के वर्षों में जिस प्रकार अपनी क्षमता सिद्ध की है, वह भारत के खेल भविष्य की सबसे सकारात्मक तस्वीरों में से एक है। महिला हॉकी की स्वर्णिम सफलता इसका ताजा उदाहरण है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, एथलेटिक्स, गोल्फ और अन्य खेलों में भी बेटीयों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। अब जरूरत है कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों

की बेटीयों को खेलों से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। सुरक्षित खेल परिसर, महिला प्रशिक्षक, छात्रवृत्ति और परिवारों में खेल के प्रति सकारात्मक वातावरण इस दिशा में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। भारत की आधी आबादी को खेल शक्ति में पूरी तरह शामिल किए बिना विश्व की खेल महाशक्ति बनने का सपना अधूरा रहेगा।

लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 दूर नहीं है। इसलिए एशियाड की उपलब्धियों और कमियों का विश्लेषण केवल समाचारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक खेल के लिए अभी से पदक की वास्तविक संभावना,संभावित खिलाड़ियों की सूची, प्रशिक्षण योजना और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का कैलेंडर तैयार होना चाहिए। हमें उन खेलों की पहचान करनी होगी जिनमें भारत अगले ओलंपिक में बड़ी छलांग लगा सकता है। साथ ही जिन खेलों में हम लगातार पिछड़ रहे हैं, वहां रणनीतिक निवेश करना होगा। लक्ष्य यह होना चाहिए कि भारत केवल कुछ पारंपरिक खेलों में नहीं, बल्कि एथलेटिक्स, तैराकी, निशानेबाजी, जिम्नास्टिक, साइकिलिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी और अन्य ओलंपिक खेलों में व्यापक पदक क्षमता विकसित करे। भारत का चौथा स्थान यह संदेश देता है कि हम पीछे नहीं हैं ।

सीट नहीं,सियासी जीत की लड़ाई,कांग्रेस-सपा को गठबंधन के भीतर विश्वास की जरूरत



मौरभ वार्धन
 दिल्ली

समझ नहीं आता कि राजनीतिक पार्टी हर बार चुनाव से पहले कसमस में क्यों उलझ कर रह जाती है। जहां एक ओर आगामी युवा देश की कमान ऐसे नेता को सौंपना चाहता है जो उनका नेतृत्व कर सकें। वहीं चुनाव पूर्व रणनीति को समझने की जगह जनता के सेंटीमेंट को समझ ही नहीं पा रही ? फिर चुनाव बाद पश्चाताप करते दिखाई हैं जैसे ममता दीदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगमी बढने के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह की खींचतान सामने आ रही है, उसने विपक्षी एकता के दावों की वास्तविकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर दोनों दल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मजबूत राजनीतिक चुनौती पेश करने की तैयारी में जुटे हैं,दूसरी ओर गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या,राजनीतिक प्रभाव और नेतृत्व की प्राथमिकताओं को लेकर अक्सरता लगातार सामने आ रही है। सवाल केवल यह नहीं है कि सपा कितनी सीटें चाहती है और कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा कर रही है। असली सवाल यह है कि क्या दोनों दल उस राजनीतिक समझ और परिपक्वता का परिचय दे पाएंगे,जिसकी अपेक्षा एक प्रभावी गठबंधन से की जाती है?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह कहना कि बात सीट की नहीं, जीत की है इसके मायने अलग हैं वह समझ रहे है कि बिना गठबंधन के कुछ नहीं हो सकता? इस पूरे विवाद के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है। उन्होंने गठबंधन की जीत को सीटों की संख्या से ऊपर रखते हुए कहा कि मकसद स्पष्ट हो तो साथ मिलकर मंजिल हासिल की जा सकती है। उनका यह संदेश सपा-कांग्रेस के बीच चल रही

खींचतान के बीच एक तरह से राजनीतिक संयम की अपील भी है। लेकिन राजनीति में केवल संदेश काफी नहीं होते। संदेश को जमीन पर उतारने की इच्छाशक्ति और संगठनात्मक क्षमता भी चाहिए। यही वह बिंदु है जहां सपा-कांग्रेस गठबंधन की असली परीक्षा शुरू होती है।

चुनावी गठबंधन कोई ऐसा समझौता नहीं होता जिसमें केवल सीटों का गणित बैठा दिया जाए। गठबंधन का अर्थ है कि एक-दूसरे के राजनीतिक अस्तित्व का सम्मान,साझा रणनीति,कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और मतदाताओं को एक स्पष्ट संदेश। यदि शीर्ष नेतृत्व मंच पर एकता की बात करे, लेकिन स्थानीय स्तर पर दोनों दलों के नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयान दें,तो जनता के बीच गठबंधन की विश्वसनीयता स्वाभाविक रूप से कमजोर होगी। उत्तर प्रदेश में यह खतरा और भी बड़ा है,क्योंकि यहां चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं,बल्कि सामाजिक और क्षेत्री समीकरणों के बीच भी लड़ा जाता है। प्रत्येक सीट का अपना अलग सामाजिक समीकरण,स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक इतिहास होता है। ऐसे में केवल सीटों की संख्या के आधार पर फार्मूला तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा। यह देखना होगा कि किस क्षेत्र में किस दल का संगठन मजबूत है, किस उम्मीदवार की स्वीकार्यता अधिक है और कौन-सा प्रत्याशी विपक्षी मतों को एकजुट कर सकता है।

यही वह व्यावहारिक राजनीति है जिसे समझे बिना गठबंधन का गणित कागज पर तो सुंदर दिखाई दे सकता है, लेकिन चुनावी मैदान में बिखर सकता है। भाजपा ने सपा-कांग्रेस के बीच जारी मतभेदों को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश निपाटी का गठबंधन को लठबंधन कहना इसे रणनीति का हिस्सा है। भाजपा के लिए विपक्षी गठबंधन के भीतर का प्रत्येक मतभेद राजनीतिक अवसर है। विपक्ष जितना अधिक एक-दूसरे के खिलाफ बोलेगा,भाजपा उतना ही यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसके सामने खड़ा गठबंधन सत्ता का विकल्प बनने से पहले ही आपसी संघर्ष

में उलझ गया है। भाजपा के खिलाफ लड़ाई केवल चुनावी भाषणों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए विपक्षी दलों को अपने भीतर की कमजोरियों पर भी विजय हासिल करनी होगी। यह विडंबना है कि जो दल लोकतंत्र, संविधान,सामाजिक न्याय और जनहित के बड़े मुद्दों को लेकर एक मंच पर आने की बात करते हैं,वे स्वयं सीटों के प्रश्न पर सार्वजनिक असहमति का प्रदर्शन करने लगे। जनता स्वाभाविक रूप से पूछेगी कि जब सत्ता की साझेदारी अभी हुई भी नहीं है तो सीटों की साझेदारी पर इतना संघर्ष क्यों?

दरअसल,गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ा संकट सीटों की संख्या नहीं,विश्वास का संकट होता है। यदि सपा को कांग्रेस पर और कांग्रेस को सपा पर भरोसा नहीं होगा तो कोई भी सीट समझौता स्थायी नहीं हो सकता। आज एक फार्मूला तय होगा,कुल उम्मीदवार चयन पर विवाद होगा और चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की समस्या सामने आएगी। ऐसी स्थिति में गठबंधन का लाभ विपक्षी दल को मिल सकता है। इसलिए दोनों दलों को यह स्वीकार करना होगा कि गठबंधन में किसी एक दल की पूर्ण राजनीतिक संतुष्टि संभव नहीं होती। गठबंधन में समझौते करने पड़ते हैं। कुछ सीटें छोड़नी पड़ती हैं ताकि अधिक सीटें जीती जा सकें। राजनीति में कभी-कभी कम सीटों पर लड़ना,अधिक सीटें जीतने की रणनीति भी हो सकती है। इसके विपरीत अधिक सीटों पर लड़ने का अहंकार कई बार जीत की संभावनाओं को ही कमजोर कर देता है। अखिलेश यादव का बात सीट की नहीं,जीत की है वाला कथन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें गठबंधन की राजनीति का मूल तत्व छिपा हुआ है। यदि सपा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपने-अपने राजनीतिक विस्तार की चिंता के साथ-साथ साझा राजनीतिक लक्ष्य पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन कांग्रेस की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपने संगठन और राजनीतिक प्रभाव को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

मतदाता सूची से जंतर-मंतर तक: लोकतंत्र के भरोसे की अग्निपरीक्षा



योगेश कुं0 गोयल
 नई दिल्ली

प्रभावित हुए हैं और इससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता-सूचियों को शुद्ध और अद्यतन करना है तथा दलगत तरीके से छूट गए पात्र मतदाताओं को फिर शामिल करने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। आयोग ने अब 20 राज्यों और

केवल भौड़, राजनीतिक प्रदर्शन या कानून-व्यवस्था की समस्या मान लेना, लोकतांत्रिक विमर्श को छोटा करना होगा।

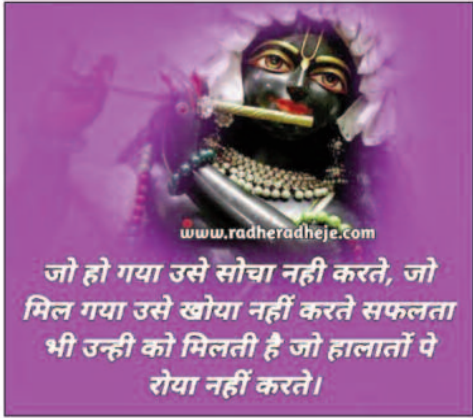
मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं और इससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता-सूचियों को शुद्ध और अद्यतन करना है तथा दलगत तरीके से छूट गए पात्र मतदाताओं को फिर शामिल करने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। आयोग ने अब 20 राज्यों और

केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान और पुनः नामांकन के लिए विशेष अभियान की घोषणा की है। यही वह बिंदु है, जहां राजनीतिक आरोपों और संस्थागत तथ्यों को गहराई से देखना आवश्यक है। जब मतदाता-सूची जैसी लोकतंत्र की बुनियादी व्यवस्था पर व्यापक संदेह पैदा हों तो निर्वाचन आयोग पर केवल यह कहकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता कि वह संवैधानिक संस्था है, इसलिए उस पर विश्वास किया जाए। संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठ अधिकार से नहीं,पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से मजबूत होती है।

वर्तमान विवाद का सबसे ठोस और जांच योग्य पहलू फॉर्म-6 से जुड़ा है। फॉर्म-6 मतदाता सूची में नाम शामिल करने का निर्धारित आवेदन है। विवाद तब उठा,जब एसआईआर से संबंधित एक

अतिरिक्त घोषणा ऑनलाइन फॉर्म-6 में जोड़े जाने पर आयोग के भीतर ही दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां सामने आईं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार,चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस बदलाव की वैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिसके बाद आयोग ने 30 सितंबर को उन राज्यों में,जहां एसआईआर पूरा हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म-6 से यह अतिरिक्त घोषणा हटा दी। यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि घोषणा-पत्र हटाया गया या नहीं बल्कि यह है कि उसे जोड़ा किस अधिकार के तहत गया, किस स्तर पर स्वीकृति मिली,उसका तकनीकी क्रियान्वयन किस आदेश पर हुआ और बाद में उसे हटाया का निर्णय किस प्रक्रिया से लिया गया? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर सार्वजनिक होने चाहिए।

सुविचार



जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते सफलता भी उन्ही को मिलती है जो हालातों पे रोया नहीं करते।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

—सम्पादक

CMYK



सूरजपुर में 'जल, जन सेवा संकल्प यात्रा' का भव्य स्वागत 500 भाजयुमो बाइकर्स ने बढ़ाया कारवां

वडनगर से वाराणसी जा रही यात्रा का लाभार्थी सम्मेलन, अग्रसेन चौक पर पुष्पवर्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गंगा आरती और 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत 100 से अधिक पौधों का रोपण

500 बाइकर्स के साथ सूरजपुर पहुंची 'जल,जन सेवा संकल्प यात्रा',शहर में दिखा युवाओं का उत्साह

बाइकर्स का लंबा कारवां,जगह-जगह स्वागत...सूरजपुर में 'जल,जन सेवा संकल्प यात्रा' का भव्य आगमन

वडनगर से वाराणसी तक सेवा का संकल्प,सूरजपुर में 500 बाइकर्स ने संभाली यात्रा की कमान

बाइक रैली से गुंजा सूरजपुर, 'जल, जन सेवा संकल्प यात्रा' में 500 भाजयुमो बाइकर्स शामिल

—ऑकर पाण्डेय—
सूरजपुर,05 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा निकाली जा रही 'जल,जन सेवा संकल्प यात्रा' के सूरजपुर जिले में पहुंचने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, गुजरात के वडनगर से वाराणसी की ओर बढ़ रही यात्रा के रूट क्रमांक-1 के तहत जिले में प्रवेश करने वाले यात्रा दल का स्थानीय स्तर पर स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान लाभार्थी सम्मेलन, बाइक रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गंगा आरती और पौधरोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। यात्रा की तैयारियों और स्थानीय रूट को लेकर पहले भी भाजयुमो के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने सूरजपुर पहुंचकर रूट का स्थलीय निरीक्षण किया था। आयोजकों के अनुसार,सूरजपुर में यात्रा के स्वागत और विभिन्न कार्यक्रमों का नेतृत्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता ने किया,उन्होंने नेतृत्व में जिले के करीब 500 स्थानीय बाइकर्स यात्रा में शामिल हुए, इससे यात्रा के स्थानीय कार्यक्रम को बड़ी स्वरूप मिला,यात्रा के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित रूटों में सेवा,पर्यावरण संरक्षण, जनसंवाद और सामाजिक सहभागिता से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया गया है।

कृष्णपुर-कलुआ में लाभार्थी सम्मेलन,योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद- यात्रा के सूरजपुर जिले में पहुंचने के दौरान दोपहर में कृष्णपुर-कलुआ क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया, सम्मेलन में वडनगर से यात्रा के साथ आए

अग्रसेन चौक पर पुष्पवर्षा और ढोल-नगाड़ों से स्वागत

दोपहर बाद यात्रा के सूरजपुर पहुंचने पर अग्रसेन चौक में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, यहां यात्रा दल के पहुंचने पर पुष्पवर्षा की गई और ढोल-नगाड़ों के साथ राइडर्स का स्वागत किया गया, स्थानीय भाजयुमो कार्यकर्ताओं और बाइकर्स की बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण चौक पर उत्साह का माहौल रहा,जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे युवा कार्यकर्ताओं ने यात्रा में सहभागिता की, यात्रा के स्थानीय रूट को लेकर इससे पहले आयोजित तैयारियों में भी कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं और यात्रा के दौरान युवा संवाद, लाभार्थियों से संपर्क, पर्यावरण संरक्षण तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल करने की रूपरेखा बनाई गई थी।

अर्बन कैफे में सांस्कृतिक कार्यक्रम,राइडर्स का सम्मान

शाम को अर्बन कैफे, सूरजपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, इसके बाद यात्रा में शामिल अतिथि राइडर्स को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया, गुजरात से विशेष रूप से यात्रा में शामिल हुए भागव जनी, धुवीण पटेल सहित 31 राइडर्स की कार्यक्रम में सहभागिता रही, स्थानीय आयोजकों और कार्यकर्ताओं ने यात्रा दल के साथ संवाद किया और यात्रा की आगे की गतिविधियों के लिए शुभकामनाएं दीं।

भागव जनी ने शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद किया,इस दौरान महतारी वंदन योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ग्रामीण आवास योजना,उज्ज्वला योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए,आयोजकों के अनुसार, लाभार्थियों ने योजनाओं से प्राप्त लाभ की जानकारी यात्रा में शामिल लोगों के साथ साझा की और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया,इस संवाद का उद्देश्य यात्रा को केवल बाइक रैली तक सीमित न रखते हुए योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों और यात्रा दल के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना बताया गया।

बनारस की तर्ज पर गंगा आरती, भक्तिमय हुआ माहौल-सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद गंगा आरती का आयोजन किया गया, आयोजकों के अनुसार,बनारस से आए पुरोहितों की टीम ने गंगा आरती की प्रस्तुति वाराणसी की शैली में की,आरती के दौरान वातावरण भक्तिमय रहा,आरती के बाद यात्रा में शामिल अतिथियों और राइडर्स के लिए रात्रि भोज एवं विश्राम की व्यवस्था की गई, इस आयोजन के माध्यम से यात्रा के सामाजिक एवं पर्यावरणीय संदेश के साथ

धार्मिक-सांस्कृतिक पक्ष को भी कार्यक्रम में जोड़ा गया।

सरना परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम', 100 से अधिक पौधे रोपे-यात्रा के तहत सूरजपुर नगर के वार्ड क्रमांक-02 स्थित सरना परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, कार्यक्रम का उद्देश्य पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण,हरियाली विस्तार और जल संरक्षण का संदेश देना बताया गया,सरना देव स्थल परिसर में 100 से अधिक फलदार एवं छयादार पौधे लगाए गए,इनमें लीची,आम, जामुन, आंवला, गुलमोहर और कदम सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे शामिल रहे,कार्यक्रम में यात्रा के साथ गुजरात से पहुंचे 31 राइडर्स ने भी पौधरोपण किया, स्थानीय भाजयुमो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पौधे लगाए, 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को संचालित किया गया,वर्षा दूसरी ओर बाइक रैली सेवा संकल्प से जोड़ते हुए आयोजकों ने पौधों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया।

देव गुप्ता ने बताया वृक्षों का महत्व- भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता ने पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान वृक्षों के महत्व पर प्रकाश



छला,उन्होंने कहा कि पेड़ मानव जीवन और पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन का महत्वपूर्ण आधार हैं,वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं,उन्होंने कहा कि पेड़ जल चक्र को बेहतर बनाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और वन्यजीवों को आश्रय उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण हैं, उनके अनुसार,पौधरोपण केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि लगाए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी इसके साथ जुड़ी है, उन्होंने लोगों से प्रकृति संरक्षण में भागीदारी करने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया।

एक ही यात्रा में सेवा, संवाद और पर्यावरण का संदेश-सूरजपुर में आयोजित कार्यक्रमों में यात्रा को कई गतिविधियों से जोड़ा गया, एक ओर जहां लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद किया गया,वर्षा दूसरी ओर बाइक रैली के माध्यम से युवाओं की सहभागिता दिखाई गई,शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और गंगा आरती आयोजित हुईं तो अगले कार्यक्रम में पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया,भाजयुमो के राष्ट्रीय स्तर के इस अभियान के विभिन्न मार्गों पर भी

पौधरोपण,स्वच्छता,जनसंवाद और सामाजिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

भाजपा और भाजयुमो के पदाधिकारी रहे मौजूद-कार्यक्रमों में प्रेमनगर विधायक भुलन सिंह मरावी,भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी,भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा,प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम जायसवाल,प्रदेश मंत्री प्रिया सिंह,जिला सहप्रभारी आनंद ताम्रकार,पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रामकृपाल साहू,पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अजय गोयल, प्रदेश अध्यक्ष अजजा मोर्चा सत्यनारायण सिंह,भाजपा महामंत्री शशिकांत गर्ग,भाजपा कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल,जिला मंत्री राजेश्वर तिवारी,जिला मंत्री दीपक गुप्ता,अजजा मोर्चा जिलाध्यक्ष कौशल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, भाजयुमो की ओर से जिला महामंत्री यशवत सिंह, रूपेंद्र कुशवाहा,जिला उपाध्यक्ष अविनाश सहवाल,जिला मंत्री सहीम अंसारी,सत्यम विश्वकर्मा,मितल पाण्डेय,सुजीत सिंह,जिला मीडिया प्रभारी दीक्षित वर्मा,जिला कार्यालय मंत्री सोनू साहू,विशाल गुप्ता,रीशन गुप्ता,विष्णु सोनी,राजकुमार यादव,संजीव गुप्ता, हरिनारायण साहू,मंदू गुप्ता,बंटी ठाकुर,शैलेंद्र कुशवाहा और हर्ष गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल

रहे,पौधरोपण कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की भी मौजूदगी रही,उनके साथ विधायक भुलन सिंह मरावी, भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी तथा भाजपा एवं भाजयुमो के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी

आयोजकों के अनुसार,यात्रा के स्वागत कार्यक्रमों में भाजपा जिला पदाधिकारियों, सदस्यों,विशेष आमंत्रित सदस्यों तथा विभिन्न मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं ने भी सहभागिता की,स्थानीय स्तर पर 500 बाइकर्स की भागीदारी को यात्रा के प्रमुख आकर्षण के रूप में देखा गया,वर्षा गुजरात से आए 31 राइडर्स ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया,यात्रा की तैयारियों को लेकर इससे पहले सूरजपुर में भाजयुमो के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया था,उस दौरान केवरा,करोंटी बी,चंदौर,खड़गांवकला और अमननदी सहित प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया था।

सेवा संकल्प को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास

सूरजपुर में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए यात्रा को केवल राजनीतिक संगठन की बाइक यात्रा के बजाय लाभार्थी संवाद,पर्यावरण संरक्षण,सांस्कृतिक सहभागिता और धार्मिक आयोजन से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, आयोजकों ने इसे सेवा,जल संरक्षण, जनसहभागिता और हरियाली के संदेश से जोड़ते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिले में सितंबर से अक्टूबर तक चल रहे व्यापक 'एक संकल्प अभियान' के तहत भी अलग-अलग स्तर पर सेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिले में अभियान की अवधि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित किए जाने की जानकारी पूर्व में सामने आई थी।

प्रेम संबंध में पति बना बाधक तो पति-पत्नी ने रची हत्या की साजिश

फोन कर युवक को बुलाया,कुलुवरी से हत्या के बाद सिर-थड़ अलग कर जंगल में फेंका,तापता होने के 24 घंटे में खुलासा

—संवाददाता—

बलरामपुर,05 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के डौरा क्षेत्र में तापता युवक की हत्या का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या किसी अनजान हमलावर ने नहीं,बल्कि एक महिला और उसके पति ने मिलकर की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला के मृतक युवक से कथित प्रेम संबंध थे। इसके बाद दोनों ने युवक को फोन कर बुलाया और कुलुवरी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए सिर और थड़ अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिए गए। मामले में पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम कोदौरा निवासी वसीम अंसारी 2 अक्टूबर को शाम एक्टिवा स्कूटी क्रमांक CG15CQ3388 लेकर घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन 3 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे उसकी स्कूटी गांव के पास मक्का बाड़ी के नजदीक लावारिस हालत में मिली। युवक का कोई सुरांग नहीं मिलने पर उसके बड़े भाई असीम अंसारी ने डौरा चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। युवक की तलाश के दौरान पुलिस को ग्राम भीतर चिल्मा के उबका जंगल में नाले के पास एक गड्ढे में मानव सिर पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव के हिस्से को बरामद किया। मृतक के भाई ने उसकी पहचान वसीम अंसारी के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या से जोड़कर जांच तेज कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर ग्राम कोटडीह निवासी सोनू खैरवार और उसकी पत्नी मनबासो को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पृष्ठताछ में मनबासो ने मृतक के साथ पूर्व से संबंध होने की बात बताई।



नर्मदापुर में सेवा सेतु शिविर आयोजित...शिविर में प्राप्त हुए 102 आवेदन, हितग्राहियों को बी-1, स्प्रेयर एवं रेडी-टू-ईट का किया गया वितरण

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,05 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा सेतु अभियान के तहत मैनापाट विकासखण्ड के ग्राम पंचायत नर्मदापुर स्थित स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में खण्ड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही एवं निराकरण के लिए प्रेषित किया गया। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा श्री सुमन नाग, श्री कृष्णा, श्री भंगी, श्री बोरबल, श्री परसराम, श्री मनीराम एवं श्री पंखरा को बी-1 का वितरण किया गया। कृषि विभाग द्वारा श्रीमती धनेश्वरी पन्ना, श्रीमती



अनिता, श्रीमती उमावती, श्री शिवराम एवं श्री जमुना प्रसाद को स्प्रेयर का वितरण किया गया। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा श्रीमती चुन्नी, श्रीमती

एतसारी, श्रीमती सुखनी, श्रीमती शनियारो, श्रीमती विधनी, श्रीमती सावित्री, श्रीमती शोकरपति एवं नईशार को रेडी-टू-ईट प्रदान किया गया।

विभिन्न विभागों से संबंधित 102 आवेदन प्राप्त : शिविर में राजस्व विभाग के 07, खाद्य विभाग के 15, पंचायत विभाग के 45, महिला एवं बाल विकास

विभाग का 01, लोक निर्माण विभाग के 02, कृषि विभाग का 01,लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग के 03,समाज कल्याण विभाग के 13,शिक्षा विभाग के 02, विद्युत विभाग के 04 तथा क्रेड का 09 आवेदन सहित कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों को आवश्यक कार्यवाही एवं समयबद्ध निराकरण के लिए संबंधित विभागों को सौंपा गया।

इस अवसर पर जन प्रतिनिधि श्री रजनीश पाण्डेय, श्री जमुना यादव, श्री शंकर यादव,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतापुत्र,तहसीलदार मैनापाट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनापाट सहित महिला एवं बाल विकास,कृषि,विद्युत,आदिम जाति कल्याण,स्वास्थ्य,राजस्व,खाद्य,मत्स्य, शिक्षा एवं श्रम विभाग के अधिकारी-कर्मचारी,ग्राम पंचायत नर्मदापुर के सरपंच तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

पानी समझकर बच्चा पी गया महुआ शराब,इलाज के दौरान हो गई मौत...

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,05 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

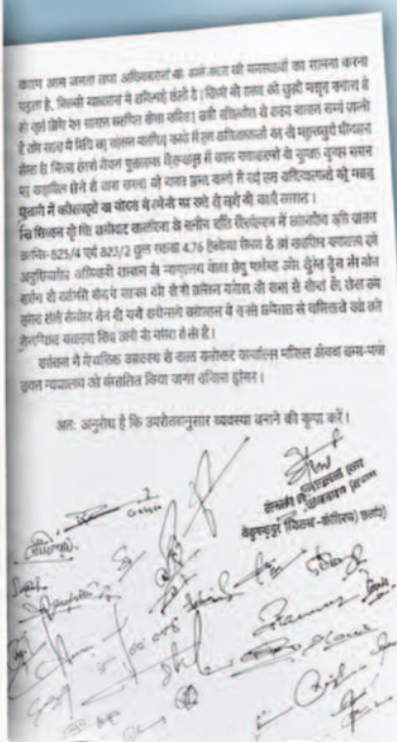
पानी समझकर महुआ शराब का सेवन किए मासूम बच्चे की अस्पतालों का चक्कर काटते

इलाज के दौरान मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक,कोरवा जिले के दुलापुर, काशीमुड़ा,पसान कोरबी निवासी शिवलाल सिंह का 3 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार सिंह बीते

29 सितम्बर को घर में ही खेल रहा था। शाम को करीब 4 बजे खेलते समय एक बोतल में रखे महुआ शराब को पानी समझकर पी लिया, इससे स्वजन अनभिज्ञ थे। बच्चे को उल्टी करते मां ने देखा और शाम को पति के घर

पहुंचने पर वह बच्चे के द्वारा उल्टी करने और महुआ शराब का गंध आने की जानकारी दी। 30 सितम्बर को बच्चे का तबियत खराब देखकर स्वजन उसे खड़ावां स्वास्थ्य केंद्र ले गए, यहां से रेफर करने पर चिरमिरी ले गए।

बच्चे का स्वास्थ्य खराब देखकर चिकित्सक ने यहां से भी रेफर कर दिया। इलाज के दौरान 4 अक्टूबर को बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मृत बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।



उद्घाटन के लिए गाड़ी ने लिया ‘अवतार’, कार्यक्रम खत्म होते ही हुई ‘अदृश्य’? आरटीआई के जवाब ने खड़ा कर दिया ‘अवतार’ और ‘गायब’ वाहन का सवाल

सरकारी रिकॉर्ड में वाहन खरीदी नहीं, ‘इको विकास समिति लोलकी’ का भी अता-पता नहीं, फिर वीवीआईपी कार्यक्रम में गाड़ी पर समिति का नाम कैसे आया?

न खरीदी का रिकॉर्ड, न समिति का अस्तित्व... फिर किस गाड़ी का हुआ लोकार्पण?

गाड़ी खरीदी नहीं गई, समिति बनी नहीं... फिर उद्घाटन के दिन गाड़ी आई कहां से?

उद्घाटन के दिन गाड़ी मौजूद, रिकॉर्ड में खरीदी गायब...

‘इको विकास समिति लोलकी’ भी सवालों में...

गाड़ी आई, फूल-माला सजी, लोकार्पण हुआ... फिर

गाड़ी गई कहां? आरटीआई ने पूछा हिसाब

न समिति का पता, न वाहन खरीदी का रिकॉर्ड... फिर

किसके नाम पर हुआ वीवीआईपी लोकार्पण?

आरटीआई ने बढ़ाई उलझन: गाड़ी खरीदी नहीं तो

आई कहां से, समिति थी नहीं तो नाम आया कैसे?

सरकारी रिकॉर्ड में वाहन खरीदी नहीं, ‘इको विकास समिति लोलकी’ का अस्तित्व भी

नहीं, फिर वीवीआईपी लोकार्पण में वाहन पर समिति का नाम कैसे आया?

दैनिक घटती-घटना लगातार उठा रहा मामला, अब शासन-प्रशासन की जवाबदेही पर नजर

राजन पाण्डेय

बैकग्राउंड, 05 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

कभी-कभी सरकारी फाइलें ऐसे सवाल खड़े कर देती हैं, जिनका जवाब तलाशते-तलाशते पूरा मामला व्यंग्य का रूप ले लेता है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में जून 2022 में हुए कथित वीवीआईपी पर्यटक वाहन लोकार्पण का मामला भी अब कुछ ऐसा ही सवाल बनकर सामने आया है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार, संबंधित वाहन की शासकीय खरीदी का रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, दूसरी ओर, जिस ‘इको विकास समिति लोलकी’ के नाम का उल्लेख वाहन पर किया गया था, उसके गठन अथवा संचालन की जानकारी भी विभागीय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है, अब सवाल सीधा है की जब समिति थी ही नहीं और वाहन खरीदा ही नहीं गया, तो फिर उद्घाटन के दिन वाहन आया कहां से? और यहीं से शुरू होता है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा व्यंग्य, वाहन ने शायद खुद ही ‘अवतार’ लिया था! मान लीजिए विभाग ने वाहन खरीदा नहीं था, तो फिर उद्घाटन के दिन वह वाहन वहां पहुंचा कैसे? क्या वह किसी निजी व्यक्ति का था? क्या किसी एजेंसी से किराए पर लिया गया था?

क्या किसी अन्य संस्था या योजना का वाहन था? या फिर वह केवल वीवीआईपी लोकार्पण के लिए कुछ समय के लिए ‘अवतार’ लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा और कार्यक्रम समाप्त होते ही फिर अपने मूल लोक में वापस चला गया? व्यंग्य इसलिए बनता है क्योंकि आरटीआई के जवाब ने सवालों को खत्म करने के बजाय और ज्यादा गहरा कर दिया है, अगर वाहन किराए पर आया

और ‘इको विकास समिति लोलकी’... यह समिति भी जैसे उद्घाटन के दिन ही पैदा हुई थी?

मामले का दूसरा सवाल वाहन से भी ज्यादा दिलचस्प है, वाहन पर ‘इको विकास समिति लोलकी’ का नाम लिखा था, लेकिन आरटीआई से सामने आई जानकारी के अनुसार विभाग के पास इस नाम से समिति के गठन या संचालन की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो फिर सवाल यह है कि जब समिति का सरकारी रिकॉर्ड में पता नहीं, तो वाहन पर उसका नाम किस आधार पर लिखा गया? क्या समिति बनाने का प्रस्ताव था? क्या समिति बनने वाली थी? क्या नाम केवल कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया गया? क्या किसी ग्रामसभा की बैठक हुई थी? क्या समिति की सदस्य सूची थी? क्या उसका बैंक खाता था? क्या संचालन के लिए कोई आदेश जारी हुआ था? अगर इनमें से कुछ भी नहीं था तो फिर वाहन पर समिति का नाम लिखे जाने की कहानी और भी उलझ जाती है, यानी एक तरफ वाहन का खरीद रिकॉर्ड नहीं, दूसरी तरफ समिति का गठन रिकॉर्ड में नहीं, लेकिन उद्घाटन के दिन दोनों मौजूद—वाहन भी और समिति का नाम भी, यही वह बिंदु है जहां पूरा मामला सरकारी व्यवस्था से एक अजीब-सा सवाल पुछता दिखाई देता है क्या सरकारी योजनाओं में कभी-कभी पहले उद्घाटन हो जाता है और उसके बाद कागज तलाशे जाते हैं? बेशक, यह केवल व्यंग्यात्मक सवाल है। वास्तविक उत्तर दस्तावेजों की जांच के बाद ही मिल सकता है।

था तो किराए का रिकॉर्ड कहां है? अगर निजी वाहन था तो मालिक कौन था? अगर किसी एजेंसी ने उपलब्ध कराया था तो उसका अनुबंध कहां है? अगर किसी दूसरी सरकारी योजना का वाहन था तो उसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की पहल के रूप में किस आधार पर प्रस्तुत किया गया? इन सवालों का जवाब अभी जांच और दस्तावेजों के परीक्षण से ही सामने आ सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि वाहन के वास्तविक स्रोत और उपयोग की कहानी स्पष्ट किए जाने की जरूरत बढ़ गई है।

उद्घाटन हुआ तो फिर उद्घाटन किस चीज का हुआ?— जून 2022 के कार्यक्रम की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रभारी सचिव, कलेक्टर और

वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी थी, ऐसे वीवीआईपी कार्यक्रम में जिस योजना, वाहन या व्यवस्था को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उसके पीछे प्रशासनिक तैयारी और दस्तावेज होना स्वाभाविक अपेक्षा है, अब अगर रिकॉर्ड कहता है कि वाहन खरीदा नहीं गया, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि उद्घाटन आखिर किस आधार पर हुआ?

उद्घाटन के बाद वाहन गया कहां?— यह सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, अगर वाहन ‘इको-टूरिज्म’ के लिए था, तो उसके बाद उसकी लॉगबुक कहां है? किसके नाम पर वाहन था? उसका आरसी कहां है? चेसिस नंबर और इंजन नंबर क्या था? बीमा किसके नाम पर था? फिटनेस प्रमाणपत्र किसके पास था? चालक कौन था? इधन का



भुगतान किस मद से हुआ? वाहन कहां-कहां चला? कितने पर्यटक उसमें बैठे? किसके खाते में आय जमा हुई? और सबसे बड़ा सवाल—अगर वाहन सरकारी खरीदी का नहीं था तो उसे कार्यक्रम के बाद वापस किसके पास भेज दिया गया? क्योंकि अगर वाहन वास्तव में ‘इको-टूरिज्म’ व्यवस्था का हिस्सा था तो उसके बाद उसका संचालन भी किसी न किसी रिकॉर्ड में होना चाहिए, विभागीय रिकॉर्ड, वाहन की लॉगबुक, अनुमति, इंधन व्यय और चालक संबंधी भुगतान जैसे दस्तावेज इस पूरी कहानी को साफ कर सकते हैं।

अगर किराए की गाड़ी थी तो किराए का हिसाब भी तो होगा?— यही वह सवाल है जो पूरे प्रकरण को और रोचक बनाता है, मान लेते हैं कि विभाग ने वाहन खरीदा ही नहीं और किसी निजी व्यक्ति या एजेंसी से वाहन लिया गया, तो फिर किराया कितना था? किसने भुगतान किया? किस मद से भुगतान हुआ? बिल किसने लगाया? भुगतान वाउचर कहां है? किस अधिकारी ने अनुमति दी? किस तारीख से वाहन लिया गया? कार्यक्रम खत्म होने के बाद वाहन कहां गया? यदि भुगतान हुआ तो कैशबुक या बैंक रिकॉर्ड में उसका उल्लेख होना चाहिए, यदि भुगतान नहीं हुआ तो वाहन मुफ्त में किसने उपलब्ध कराया और क्यों? यहां सवाल केवल वाहन का नहीं रह जाता। सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का हो जाता है।

‘गाड़ी आई, उद्घाटन हुआ और फिर गायब’— यह कहानी दस्तावेज मांगती है— गाड़ी खरीदी नहीं गई, लेकिन उद्घाटन हो गया, समिति बनी नहीं, लेकिन उसका नाम वाहन पर आ गया, गाड़ी दिखाई दी, उद्घाटन हुआ और फिर उसके बाद उसका ठिकाना सवाल बन गया, अब अगर कोई पूछे कि गाड़ी आई कहां से, तो जवाब दस्तावेजों से मिलना चाहिए, कहानी

से नहीं, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब आर.सी., चेसिस नंबर, इंजन नंबर, स्वामित्व दस्तावेज, लॉगबुक, भुगतान रिकॉर्ड, अनुमति पत्र और कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।

‘इको-टूरिज्म’ और रोजगार का सपना भी सवालों के घेरे में— इस मामले को केवल एक वाहन तक सीमित करके देखना भी उचित नहीं होगा, यदि उस समय वाहन को ‘इको-टूरिज्म’ की पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया था तो यह भी जानना जरूरी है कि उसके बाद इस व्यवस्था का क्या हुआ, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला या नहीं? स्थानीय वाहन चालकों को अवसर मिला या नहीं? गाड़ों की व्यवस्था बनी या नहीं? पर्यटकों के लिए परिवहन व्यवस्था चली या नहीं? ‘इको-टूरिज्म’ से कोई आय हुई या नहीं? किसी समिति को संचालन की जिम्मेदारी दी गई या नहीं? इन सवालों का जवाब मिलने पर पता चलेगा कि कार्यक्रम केवल उद्घाटन तक सीमित था या वास्तव में कोई व्यवस्था जमीन पर उतरी थी।

दैनिक घटती घटना लगातार उठा रहा सवाल— अब सरकार कितनी गंभीर?— इस पूरे मामले को लेकर दैनिक घटती घटना लगातार खबरें प्रकाशित कर रहा है और उपलब्ध दस्तावेजों, आरटीआई से प्राप्त जानकारी तथा सामने आए सवालों के आधार पर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, मकसद किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उन सवालों के जवाब सामने लाना है जो अब दस्तावेजों के कारण सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गए हैं, कोरिया जन सहयोग समिति ने भी पीसीसीएफ और वन सचिव को शिकायत देकर मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, समिति ने वाहन की खरीदी, पंजीयन, स्वामित्व, समिति के

गठन और लोकार्पण कार्यक्रम की प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग की है, समिति ने दस दिन के भीतर जांच की प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुए कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय जाने की बात कही है।

अब असली ‘लोकार्पण’ जवाबों का होना चाहिए...

पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी रिकॉर्ड में वाहन खरीदी नहीं है तो वह वाहन था किसका? यदि वाहन निजी था—मालिक कौन? यदि किराए का था—भुगतान कहां? यदि किसी अन्य संस्था का था—उसे यहां किस आधार पर लाया गया? यदि सरकारी योजना का था—रिकॉर्ड कहां? और यदि ‘इको विकास समिति लोलकी’ अस्तित्व में नहीं थी—तो वाहन पर उसका नाम किसने और किस आधार पर लिखा? इन सवालों के जवाब किसी राजनीतिक बयान से नहीं, दस्तावेजों से मिलने चाहिए, और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा व्यंग्य है की उद्घाटन के दिन गाड़ी मौजूद थी, गाड़ी पर समिति का नाम भी मौजूद था... अब आरटीआई के बाद सवाल यह है कि रिकॉर्ड में न गाड़ी मिल रही है, न समिति, तो फिर सवाल रहेगा की ‘गाड़ी आई कहां से... और गई कहां?’ अब निगाहें वन विभाग के उच्चाधिकारियों पर हैं, शिकायत पर समयबद्ध जांच होती है या नहीं, वाहन का वास्तविक स्वामित्व सामने आता है या नहीं और ‘इको विकास समिति लोलकी’ के नाम के इस्तेमाल का आधार स्पष्ट होता है या नहीं—इन सवालों के जवाब ही इस उलझी कहानी की अगली कड़ी तय करेंगे। फिलहाल उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामला जांच की मांग और दस्तावेज स्पष्टीकरण के स्तर पर है।

गुलाब कमरो के जन्मदिन पर दिखा जनसमर्थन... सोनहत में मरीजों के बीच पहुंचे, नागपुर में उमड़ा कार्यक्रमों का हुजूम

सोनहत से नागपुर जनकपुर तक गुंजी जन्मदिन की शुभकामनाएं, अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मिले कमरो और वितरित किए फल

—संवाददाता—

सोनहत/नागपुर, 05 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं लोकप्रिय जननेता श्री गुलाब कमरो का जन्मदिन रविवार को सोनहत और नागपुर क्षेत्र में उत्साह, आत्मीयता और जनसेवा की भावना के साथ मनाया गया, जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम नागरिकों ने विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर श्री कमरो को शुभकामनाएं दीं, इस दौरान कहीं पुष्पमालाओं से उनका आत्मीय स्वागत हुआ तो कहीं कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर जन्मदिन की खुशियां साझा कीं।

जन्मदिन समारोह की खास बात यह रही कि राजनीतिक आयोजनों तक सीमित रहने के बजाय इस अवसर को सेवा और सरोकार से जोड़ने का प्रयास किया गया, गुलाब कमरो ने सोनहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका कुशलखेम जाना, उन्होंने मरीजों के शीर्ष स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए फल वितरित किए, अस्पताल में अचानक अपने बीच पूर्व विधायक को पाकर मरीजों का कहना था कि परिजनों में भी आत्मीयता और प्रसन्नता देखने को मिली।



सोनहत में अस्पताल पहुंचकर मरीजों का जाना हाल— सोनहत में जन्मदिन के अवसर पर श्री गुलाब कमरो सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, यहां उन्होंने विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों एवं उनके परिजनों से उपचार की व्यवस्था को लेकर भी बातचीत की तथा जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दीं, इस दौरान उन्होंने मरीजों के बीच फल वितरित किए।

जन्मदिन के मौके पर अस्पताल में पहुंचकर मरीजों के साथ समय बिताने की पहल को कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जन्मदिन की भावना से जोड़कर देखा। समर्थकों का कहना था कि जन्मदिन जैसे व्यक्तिगत अवसर को जरूरतमंदों के बीच जाकर मनाया

समाज के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का संदेश देता है। **कार्यकर्ताओं ने किया आत्मीय स्वागत—** सोनहत क्षेत्र में श्री कमरो के पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाएं पहनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की, इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया, कई कार्यकर्ताओं ने श्री कमरो के साथ मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं, समर्थकों ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के साथ लंबे समय से उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर कार्यक्रमों के साथ-साथ आम नागरिकों में भी उत्साह देखने को मिला।



नागपुर में भी उमड़ा उत्साह, दीर्घायु जीवन की कामना— गुलाब कमरो के जन्मदिन को लेकर नागपुर क्षेत्र में भी कार्यक्रमों और समर्थकों में खासा उत्साह रहा, क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक एकत्र हुए और पूर्व विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि श्री कमरो ने अपने राजनीतिक जीवन में क्षेत्र के लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखा और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, उपस्थित लोगों ने उनके संघर्षशील स्वभाव, सहज व्यवहार और जनता के बीच सक्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में उनके

कार्यकाल की अनेक स्मृतियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रहती हैं। **विकास और जनसरोकारों से जुड़ी रही है राजनीति—** कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्री गुलाब कमरो की राजनीति का एक प्रमुख पक्ष क्षेत्रीय समस्याओं और विकास के मुद्दों को लेकर सक्रिय रहना रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, पुल-पुलिया सहित ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े विषयों को लेकर वे लगातार आवाज उठाते रहे हैं, जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनके सार्वजनिक जीवन और क्षेत्र के साथ उनके जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि राजनीतिक जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जनता के साथ संबंध और जनसरोकारों से जुड़ाव ही किसी नेता की वास्तविक पहचान बनाते हैं।



सोनहत से नागपुर तक बधाइयों का सिलसिला

पूर्व विधायक श्री गुलाब कमरो के जन्मदिन पर सोनहत से लेकर नागपुर क्षेत्र तक बधाइयों और शुभकामनाओं का सिलसिला चलता रहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, समर्थकों और स्थानीय नागरिकों ने उन्हें स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दीं, जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में उमड़ा उत्साह और अस्पताल में मरीजों के बीच पहुंचकर सेवा का संदेश देने की पहल ने इस आयोजन को राजनीतिक औपचारिकता से आगे बढ़ाकर जनसरोकार और आत्मीयता से जुड़ा अवसर बना दिया।

समर्थकों ने कहा... जनता के बीच बना है आत्मीय रिश्ता— सोनहत और नागपुर क्षेत्र में हुए कार्यक्रमों के दौरान समर्थकों में श्री कमरो के प्रति आत्मीयता साफ दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर अलग-अलग स्थानों से लोगों का पहुंचकर शुभकामनाएं देना इस बात का प्रतीक है कि श्री कमरो का क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ

व्यक्तिगत एवं आत्मीय रिश्ता बना हुआ है, वहीं, अस्पताल में मरीजों के बीच पहुंचकर फल वितरण किए जाने की भी लोगों ने सराहनीय पहल बताया, लोगों का कहना था कि जन्मदिन को केवल उत्सव के रूप में मनाने के बजाय जरूरतमंद और बीमार लोगों के बीच जाकर उनके सुख-दुख में सहभागी बनना समाज के प्रति संवेदनशीलता का सकारात्मक संदेश देता है।

સીલ કાર્યપાલિક દળડાધિકારી
,ભટગાંવ

सिंगापुर से छत्तीसगढ़ में 43 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव....

सिंगापुर की एनर्जी कैपिटल ग्लोबल छत्तीसगढ़ में एआई-रेडी डेटा सेंटर कैपस में करेगी 41,750 करोड़ का निवेश

रायपुर,05 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में डिजिटल सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। सिंगापुर में आयोजित SING Forum 2026 में राज्य को 43,250 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें सबसे बड़ा निवेश 41,750 करोड़ रुपए का है। सिंगापुर की कंपनी एनर्जी कैपिटल ग्लोबल छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआई-रेडी डेटा सेंटर कैपस बनाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिंगापुर में आयोजित इस फोरम में कंपनी को निवेश का न्योता सौंपा। कंपनी एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में एआई के लिए तैयार डेटा सेंटर विकसित करने और उन्हें साफ ऊर्जा से जोड़ने का काम करती है। सिंगापुर के अलावा भारत, मलेशिया, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनी की मौजूदगी है।

एआई के लिए तैयार होगा डेटा सेंटर कैपस

प्रस्तावित डेटा सेंटर कैपस की क्षमता 100 मेगावाट होगी। इसे एआई से जुड़े कामों के लिए पहले से तैयार किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक यहां बड़े स्तर पर एआई और डिजिटल सेवाओं के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पहले से देश के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में 41,750 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश राज्य को डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आगे ले जाने वाला बड़ा प्रस्ताव माना जा रहा है।



निवेश प्रस्ताव नीतियों पर भरोसे का संकेत

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ की नीतियों,यहां की क्षमता और लोगों पर कंपनियों के भरोसे को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि इन निवेशों से राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साय ने सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन की ओर से आयोजित फायरसाइड चैट में भी हिस्सा लिया। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों की समस्याओं को समझकर नियमों और व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक अब तक 450 से ज्यादा सुधार किए जा चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि सुधारों, नई औद्योगिक नीति और सरकार की सक्रिय पहल के चलते पिछले 18 महीनों में छत्तीसगढ़ को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

एनर्जी कैपिटल ग्लोबल के सीईओ स्टानिस्लाव बोयर्सोव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी बिजली, जमीन और सरकार का सहयोग उपलब्ध है। कंपनी

मध्य भारत में बड़ा एआई-रेडी डेटा सेंटर कैपस बनाने और स्थानीय इंजीनियरों को इसे संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना पर काम करेगी।



सोलर सेक्टर में भी 1,500 करोड़ का प्रस्ताव

डेटा सेंटर के अलावा छत्तीसगढ़ को सोलर सेक्टर में भी 1,500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। सनस्ट्रीम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड यह निवेश करेगी। इसमें सोलर ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज और इससे जुड़े दूसरे उपकरणों का क्षेत्र भी शामिल है। इस तरह सिंगापुर फोरम में मिले कुल निवेश प्रस्तावों में सबसे बड़ा हिस्सा एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का है।

सिंगापुर की कंपनियों से अलग-अलग बैठकें भी हुईं...

फोरम से अलग मुख्यमंत्री ने एक्वाटेक और एड्वॉन्ट ओवरसीज पीटीई लिमिटेड के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इन बैठकों में उद्योगों के लिए गंदे पानी के दोबारा इस्तेमाल की व्यवस्था और छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सिंगापुर सरकार की विदेश मामलों और व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री गण सियो हुआंग भी फोरम में मौजूद रहीं। इसके अलावा मास्टरकार्ड, IHCL (ताज होटल्स) और नैस्ले जैसी बड़ी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रमों को संबोधित किया।

आज सीईओ राउंडटेबल में होगी आगे की बातचीत

मुख्यमंत्री आज सिंगापुर की बड़ी कंपनियों और निवेश संस्थानों के प्रमुखों के साथ सीईओ राउंडटेबल में शामिल होंगे। यहां छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं और आगे की परियोजनाओं पर बातचीत होगी। सिंगापुर में हुए निवेश प्रस्तावों से छत्तीसगढ़ की कांशिश अब सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रहने वाली है। एआई, डेटा सेंटर, साफ ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग जैसे नए क्षेत्रों में भी राज्य विदेशी निवेश आकर्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

कोल घोटाला...9500 पन्नों का 6 वां पूरक चालान पेश

12 आरोपियों के नाम,विधायक देवेंद्र बोले...बीजेपी डराने और फंसाने का काम करती है...

रायपुर,05 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ से ज्यादा के कथित कोल लेवी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने सोमवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में 6वां पूरक चालान पेश किया। 9500 पन्नों का चालान 12 आरोपियों के नाम से पेश किया गया है। चालान पेन ड्राइव के जरिए पेश किया गया। चालान में राम गोपाल अग्रवाल,देवेन्द्र सिंह यादव,विनोद तिवारी,रामप्रताप सिंह,चंद्रदेव राय,जयप्रकाश मौर्य,पियूष कुमार साहू, जोगेन्द्र सिंह, अनुराग चौरसिया,दीपेश टाक, सुनील कुमार अग्रवाल और राहुल मिश्रा की घोटाले में भूमिका बताई गई है। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि कई आरोपियों को समन मिला है, जबकि कई लोगों को अभी समन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव में पेश किए गए चालान को अभी देखा नहीं गया है। इसलिए इसमें कितने गवाह हैं,इसकी जानकारी भी फिलहाल नहीं है। उन्होंने बताया कि ये अंतरिम चालान नहीं,बल्कि पूरक चालान है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 9 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। देवेंद्र ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया और संविधान पर पूरा भरोसा है,उनकी आवाज कोई दबा नहीं सकता। आम जनता जैसा हाल विपक्ष का है, प्रदेश में कुशासन है और सरकार उद्योगपतियों के सामने गिरवी रखी है। चिंतामणि महाराज को लेकर यादव ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद लोग बरी हो जाते हैं। उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्ती फंसाने और डराने का आरोप लगाते हुए कहा



आरोपों से जुड़े दस्तावेज चालान में शामिल

ईओडब्ल्यू के अनुसार,मामले में कोयला परिवहन से 25 रुपए प्रति टन की अवैध वसूली की व्यवस्था बनाई गई थी। वसूली की रकम को अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने, राजनीतिक और व्यक्तिगत कामों में खर्च करने और जमीन,वाशरी और दूसरी संपत्तियों में लगाने के आरोपों से जुड़े दस्तावेज चालान में शामिल किए गए हैं।

आदेश बदलने से लेकर वसूली तक के सबूत

जांच एजेंसी के मुताबिक, 15 जुलाई 2020 के एक आदेश के बाद कोयला परिवहन के लिए जिला खनिज अधिकारी की मंजूरी जरूरी की गई थी। ईओडब्ल्यू का दावा है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल अवैध वसूली के लिए किया गया। जांच में मोबाइल,डायरी,व्हाट्सएप चैट, बैंक लेन-देन और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। अलग-अलग जिलों में बैठकों और अधिकारियों के विश्राम गृहों में सीएम हल्लास के नाम से बुकिंग के रिकॉर्ड भी चालान में शामिल किए गए हैं।

कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, हर मोर्चे पर खड़ा रहूंगा। जेल की दीवारें मेरा इरादा नहीं तोड़ पाईं तो सरकार बया तोड़ पाएगी।

पैलेट परिवहन में 100 रुपए प्रति टन वसूली का आरोप : ईओडब्ल्यू ने कोयले के अलावा लौह अयस्क पैलेट के

परिवहन में 100 रुपए प्रति टन की वसूली का भी उल्लेख किया है। जांच के अनुसार, तत्कालीन खनिज संचालक जयप्रकाश मौर्य की भूमिका भी इस मामले में सामने आई है। आरोप है कि पैलेट कारोबारियों से सूर्यकांत तिवारी या उसके लोगों को रकम देने के निर्देश दिए गए।

9 आरोपियों को समन जारी किया गया था : पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, रामगोपाल अग्रवाल, आईएएस जयप्रकाश मौर्य और दीपेश टाक समेत 9 आरोपियों को समन जारी किया गया था। जांच में अब तक 170 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की जा चुकी है। एजेंसी का दावा है कि आईएएस जयप्रकाश मौर्य ने प्रॉपर्टी,विधायक देवेंद्र यादव ने चुनाव और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय ने ज्वेलरी में करोड़ों रुपए खर्च किए।

चिंतामणि महाराज के नाम पर भी सवाल उठाए : देवेंद्र यादव ने कहा कि शुरुआत में फाइल में चिंतामणि महाराज का नाम स्वर्ण अक्षरों में था,लेकिन बीजेपी सांसद बनने के बाद अब उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद लोग बरी हो जाते हैं और देश की जनता बीजेपी के सभी प्रपंचों को जानती है। वहीं ईडी की चार्जशीट के मुताबिक,570 करोड़ रुपए के कोल स्कैम में सबसे ज्यादा फायदा 8 नेताओं और अफसरों को मिला। आरोप है कि नेताओं और अफसरों ने कोल स्कैम के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी,गहने लिए और चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए।

बालोद में पुलिसकर्मी की बेटी पर एसिड अटैक

लाइब्रेरी से लौट रही थी,शरीर का दाहिना हिस्सा और आंख-चेहरा झुलसा

बालोद,05 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिसकर्मी की बेटी पर एसिड अटैक हुआ है। 22 साल की छात्रा आमापारा लाइब्रेरी से पढ़ाई कर घर लौट रही थी, तभी सिंचाई कॉलोनी में एक युवक ने उस पर एसिड डाल दिया। एसिड से उसके शरीर का दाहिना हिस्सा और आंख-चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। आरोपी युवक सीसीटीवी में भागते हुए नजर आया है। घटना बालोद थाना इलाके के आमापारा आत्मानंद स्कूल के सामने की है। जानकारी के मुताबिक छात्रा एमए की पढ़ाई पूरी कर चुकी है। अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। सोमवार दोपहर 12:30 को वह लाइब्रेरी से पढ़ाई कर घर लौट रही थी। इसी दौरान एक युवक ने उस पर एसिड डाल दिया। एसिड पड़ते ही छात्रा तेज जलन से चिल्लाने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार, छात्रा के शरीर का दाहिना हिस्सा बुरी तरह झुलस गया है। चेहरे और आंख के



आसपास भी जली है। पीड़िता बालोद शहर में पदस्थ एक पुलिसकर्मी की बेटी बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी युवक पैदल ही आमापारा केनाल की ओर फरार हो गया। सूचना मिलते ही टीआई, एसपी और एएसपी समेत प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि छात्रा पर हमला किस वजह से किया गया। आरोपी ने किस तरह के एसिड का इस्तेमाल किया।

रायपुर एयरपोर्ट के नए डायरेक्टर होंगे मोहम्मद आरिफ

रायपुर,05 अक्टूबर 2026। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट डायरेक्टर के रूप में मोहम्मद आरिफ की नियुक्ति की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्रधिकरण के आदेश के अनुसार वे 6 अक्टूबर 2026 से रायपुर एयरपोर्ट का कार्यभार संभालेंगे। मोहम्मद आरिफ एएआई के वाणिज्यिक विभाग से जुड़े

हैं वे विमानन और एयरपोर्ट संचालन के क्षेत्र में अनुभवी अधिकारी हैं। इससे पहले वे बागडोगरा एयरपोर्ट और कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयरपोर्ट डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। दो प्रमुख एयरपोर्ट के डायरेक्टर के रूप में काम करने के दौरान आरिफ को एयरपोर्ट संचालन, प्रशासन, यात्री सुविधाओं

और यात्री सेवाओं का अनुभव मिला है। उनके अनुभव से रायपुर एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं और सेवाओं को और बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। आरिफ के कार्यभार संभालने के बाद एयरपोर्ट के संचालन और यात्री-केंद्रित सेवाओं को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा।

पीएम मोदी के सेवाकाल के 25 साल पूरे...छत्तीसगढ़ में 7 अक्टूबर को हर विधानसभा में यात्रा,ब्लॉक-स्तर पर बनेगी केंद्र की योजनाओं वाली रंगोली

रायपुर,05 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवाकाल के 25 साल पूरे होने पर भाजपा छत्तीसगढ़ में 7 अक्टूबर को विशेष कार्यक्रम करेगी। इसके तहत प्रदेश की हर विधानसभा में सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। इसमें सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री, विधायक और सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में शामिल होंगे। यात्रा के बाद लोगों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सोमवार को कृषि मंत्री रामविचार नेताम और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मृणाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियान की जानकारी दी। नेताम ने कहा कि, मोदी के सीएम और पीएम के रूप में सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं। भाजपा इसे सेवा संकल्प अभियान के रूप में मना रही है। इसके तहत पूरे देश में एक महीने तक अलग-अलग कार्यक्रम होंगे।

हर विधानसभा में निकलेगी सेवा ज्योति यात्रा

7 अक्टूबर को प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों में सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए हर विधानसभा में किसी बड़े शहर या प्रमुख स्थान को केंद्र बनाया जाएगा। यात्रा में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा। भाजपा नेताओं के मुताबिक, यात्रा के बाद विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया



हर ब्लॉक में बनेगी बड़ी रंगोली

अभियान के तहत 7 अक्टूबर को प्रदेश के हर ब्लॉक में बड़ी रंगोली भी बनाई जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास से जुड़े कामों को दिखाया जाएगा। यानी रंगोली के जरिए लोगों को यह बताया जाएगा कि, पिछले वर्षों में केंद्र की योजनाओं से किन क्षेत्रों में काम हुआ है। राजधानी रायपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसलिए यहां बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भी शामिल होने की बात भाजपा ने कही है।

पीएम मोदी के नाम होगा संवोधन

रामविचार नेताम ने कहा कि, 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन का कार्यक्रम भी होगा। भाजपा इस दिन को विशेष दिवस के तौर पर मना रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में काम हुए हैं। किसानों से लेकर दूसरे सेक्टर तक सरकार की योजनाओं का असर दिखाई दे रहा है और वैश्विक स्तर पर भी भारत का सम्मान बढ़ा है।

जाएगा। जिला स्तर पर भी सेवा ज्योति कलश यात्रा शुरू की जाएगी। धान खरीदी से पहले गिरदावरी को लेकर उठ रहे सवालों पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। विभाग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। धान खरीदी को लेकर अधिकारी भी समीक्षा कर रहे हैं और समय-समय पर इसकी स्थिति देखी जा रही है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस के सवाल उठाने पर नेताम ने कहा कि सरकार कांग्रेस के कहने के हिसाब से काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शासन जो निर्देश देगा,उसी के अनुसार काम होगा।